लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता
श्री लालकृष्ण आडवाणी का भाषण

बिजनेस स्टेंडर्ड पुरस्कार
मुम्बई–21 जून 2008

यू.पी.ए. सरकार आई.सी.यू. में भर्ती है।

श्री टी.एन. नाइनन, बिजनेस स्टेंडर्ड के सम्पादक तथा प्रकाशक, सम्मानित पुरस्कार विजेता, देवियो और सज्जनो,

मुझे आज शाम आप लोगों के बीच उपस्थित होकर वास्तव में बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं श्री नाइनन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समारोह में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इससे मुझे भारत की वाणिज्यिक राजधानी में व्यवसायिक समुदाय और बिजनेस मीडिया के लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला है।

मैं श्रोताओं में ऐसे कई सुपरिचित चेहरों तथा लोगों को देख रहा हूं जिन्होंने अपने–अपने व्यापार और व्यवसाय में उत्कृष्टता हासिल की है, लेकिन आज नई उपलब्धियां हासिल करने वाले नये लोगों से भी मेरा परिचय कराया गया है और उनमें से कुछ इस वर्ष के बिजनेस स्टेंडर्ड पुरस्कार विजेता हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में प्रत्येक वर्ष नये–नये उद्यमों में सफलता की नई कहानियां जुड़ती जा रही हैं। इससे भारतीय व्यापार जगत की बढ़ती हुई जीवतंता का पता चलता है।

इस वर्ष के बिजनेस स्टेंडर्ड पुरस्कारों के सभी विजेताओं को मेरी हार्दिक बधाई।

मैं कुछ शब्द श्री नाइनन के बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने स्वयं भी सफलता की उल्लेखनीय कहानियां लिखी हैं। आज वे एक व्यस्त पत्रकार हैं–और उन्होंने प्रकाशक बनने के बाद भी कार्यशील पत्रकार का काम नहीं छोड़ा है–जिन्होंने अपने कैरियर में शान्तिपूर्वक तथा सुसंगत रूप से एक सफलता के बाद दूसरी सफलता दर्ज कराई है और अब वे भारत में बिजनेस पत्रकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर पर पहुंच गए हैं।

मुझे बिजनेस स्टेंडर्ड समाचार–पत्र जिसके सम्पादक श्री नाइनन हैं, के बारे में भी कुछ कहना है। यह समाचार–पत्र अपने नाम के अनुरूप शीर्ष स्तर का बिजनेस न्यूज पेपर होने के साथ–साथ अत्यधिक विश्वसनीय समाचार–पत्र के रूप में भी अपना उच्च स्तर बनाए रखने में ईमानदार रहा है। यही इस न्यूज पेपर की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह समाचारों और विचारों की दृष्टि से काफी अधिक लोगों द्वारा पढ़ा जाता है।

बिजनेस स्टेंडर्ड, श्री नाइनन और उनके सभी सहयोगी आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक सफलता हासिल करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं।

आई.सी.यू. में भर्ती सरकार

मित्रो, राजनीति पर चर्चा किए बिना आगे अपना भाषण जारी रखना मेरे लिए संभवतः ठीक नहीं रहेगा। बिजनेस स्टेंडर्ड सहित सभी समाचार–पत्रों की आज की सुर्खियों में देश के राजनीतिक हालात पर जो खबरें छपी हैं उनसे केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है : **यू.पी.ए. सरकार आई.सी.यू. में भर्ती है।** यह सरकार इस स्थिति से कैसे उबर पायेगी? यह मैं नहीं जानता क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं।

लेकिन यहां एक ऐसे डॉक्टर का मामला है जो अपनी ही सरकार को इस नाजुक हालत में खुद ले आया है।

हाल में मुद्रास्फीति की दर में 11 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जो कि 13 वर्ष का रिकार्ड है और बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे कि 13 का अंक कोई ज्यादा हितकर नहीं होता। भाजपा के हम लोग जानते हैं कि वर्ष 1996 में हमारी पहली सरकार केवल 13 दिन चली और उसके बाद वर्ष 1998 में सरकार 13 महीने ही सत्ता में रही।

जनता ने डॉ0 मनमोहन सिंह से जिन्हें एक प्रख्यात अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है, निश्चित रूप से, अर्थव्यवस्था की बेहतर व्यवस्था करने की अपेक्षा की थी। पर वे इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे।

आज की दूसरी खबर है कि सरकार किस प्रकार भारत–अमेरिकी परमाणु समझौते पर स्वयं ही हाशिये पर आ गई है।

इस समझौते के बारे में मेरी पार्टी के विचारों से सभी परिचित हैं और इसे में यहां दोहराना नहीं चाहता।

यू.पी.ए. का संकट : कांग्रेस–कम्युनिस्ट गठजोड़ के बीच अन्तर्विरोधों का परिणाम

तथापि, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मैंने राष्ट्रीय राजनीति में अपने छह दशकों के दौरान ऐसी सरकार कभी नहीं देखी जो अपने आंतरिक मतभेदों के चलते इतने लम्बे समय तक पक्षाघात की स्थिति में रही हो।

शुरू से ही यह मालूम था कि कांग्रेस और सी.पी.आई. (एम) नीत कम्युनिस्ट पार्टियां आर्थिक तथा विदेश नीतियों पर एकमत नहीं होंगे और फिर भी, वे ''पथंनिरपेक्ष ताकतों'' की एकता का झूठा दावा करने पर एकजुट हुए। सही बात तो यह है कि इन दोनों पार्टियों का असली उद्‌देश्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना है।

और अब, कांग्रेस तथा कम्युनिस्टों के बीच मतभेद स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गये हैं।

यदि सरकार परमाणु समझौता के कार्यान्वयन के लिए आगे कदम बढ़ाती है तो कम्युनिस्ट सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी।

यदि सरकार इस समझौते से एक बार फिर पीछे हटती है तो प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता और सत्ता जो कभी ऊंची नहीं रही, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।

कांग्रेसियों से मेरा सीधा सा प्रश्न है–**क्या सरकार चलाने का यही तरीका है?**

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस सरकार में कुछ बहुत ही अनुभवी मंत्री हैं लेकिन सामूहिक तौर पर कहा जाए तो मैंने पिछले छह सालों में सरकार के संचालन में इतनी अधिक अकुशलता और असक्षमता कभी नहीं देखी।

यू.पी.ए. सरकार ने अपना भाग्य स्वयं मिटा लिया है। इसने औपचारिक रूप से सत्ता से बाहर जाने से पहले ही अपनी श्रद्धांजलि स्वयं लिख ली है।

यू.पी.ए. के सत्ता से बाहर हो जाने के बाद भारत को एक मजबूत नेतृत्व के साथ एक सशक्त सरकार की जरूरत।

भारत की जनता अब यू.पी.ए. सरकार से आगे की ओर देख रही है और मुझे विश्वास है कि भारत के व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले यहां बैठे श्रोतागण भी यू.पी.ए. सरकार से आगे की ओर देख रहे होंगे।

मित्रो, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि प्रतिपक्ष का नेता होने के कारण मैं इस घटनाक्रम पर खुश होऊंगा। सच कहूं, मुझे खुशी नहीं होगी।

मुझे दुख होता है कि भारत के पास विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लिए उपलब्ध जबरदस्त क्षमता में अवसरवादी राजनीति द्वारा अड़चनें डाली जा रही है जिसका बुरा प्रभाव हम स्पष्ट रूप से इन दिनों नई दिल्ली में देख ही रहे हैं।

जब हमारा देश कई विकट चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में भारत एक कमजोर और ढुलमुल सरकार को नहीं झेल सकता।

- मुद्रास्फीति से लड़ने और आवश्यक वस्तुओं तथा आम आदमी के लिए जरूरी सेवाओं की कीमतों पर नियंत्रण पाने की चुनौती।
- विकास प्रक्रिया में और तेजी लाने की चुनौती तथा इससे भी बड़ी चुनौती आर्थिक विकास को व्यापक बनाने की है ताकि इसके लाभ सबसे पहले निर्धनतम तथा अत्यधिक उपेक्षित लोगों के पास पहुंचें। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य सिद्धांत तीन स्तरीय होना चाहिए : (**क**) गरीबी को जल्दी से जल्दी समाप्त करना; (**ख**) हरेक सक्षम व्यक्ति के लिए रोजगार के लाभप्रद अवसर सृजित करना; (**ग**) अमीर और गरीब के बीच के अंतर जो अत्यधिक बढ़ गया है, को पाटना।
- हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे से कारगर ढंग से निपटने की चुनौती।
- अब हमारी उत्तरी सीमा पर गड़बड़ फैलाने वाली घटनाओं से उपजी चुनौती भी है।
- हमारी सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताएं भी दूसरे रूप में प्रकट हुई हैं। उदाहरण के लिए, ऊर्जा सुरक्षा की समस्या जिससे हमारा देश इस समय जूझ रहा है, की ओर तत्काल ध्यान देने तथा प्रभावी समाधान ढूंढने की जरूरत है।
- मेरी हमारे वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, तथा उद्यमियों से अपील है कि वे ऐसे समाधान ढूंढे जो आयातित तेल पर भारत की निर्भरता को कम करें। आज तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऊर्जा सरंक्षण तथा ऊर्जा किफायत एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए।

इन सभी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत को एक सशक्त सरकार और एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है।

भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जिसके पास विजन हो और उस सरकार के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो।

भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो **सुशासन** के सिद्धांत के प्रति समर्पित हो—यह **विकास और सुरक्षा** दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

मैं विनम्रतापूर्वक कह सकता हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के सभी गुटों के साथ मेरी पार्टी ने वर्ष 1998 से 2004 तक 6 वर्षों के दौरान इसी तरह का शासन प्रदान करने की कोशिश की थी। श्री अटल बिहारी सरकार के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अनेक पहलें कीं। हमने नीतियों में नये दूरगामी परिवर्तन किए। उनसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई।

वस्तुतः अनेक व्यवसायी मुझसे कहते हैं कि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में जो अब प्रगति देख रहे हैं वह काफी हद तक वाजपेयी सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के कारण है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी अच्छी बातें हमारी सरकार द्वारा ही की गई थीं। मेरी सरकार दूसरी सरकार द्वारा उठाए गये अच्छे कदमों का समर्थन करने—स्वीकार करने में कभी संकोच नहीं करती है।

जैसा मैंने कहा, देश अब यू.पी.ए. सरकार से आगे की ओर देख रहा है।

मेरी पार्टी और हमारा गठबन्धन एक ऐसा सशक्त, सर्वहितैषी और सक्रिय विकल्प उपलब्ध कराने के लिए तैयार है जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिस तरह के विकल्प की आज जरूरत है।

हम भारत के उदीयमान के लिए एक एजेंडा लाएंगे

आगामी दिनों और महीनों में हम भारत के उदीयमान के लिए एक सशक्त एजेंडा लाएंगे।

- एक सशक्त और जीवन्त अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा एजेंडा जो विश्व की अर्थव्यवस्था में उतार—चढ़ाव तथा अस्थिरता का सामना कर सकें।

- कृषि को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण विकास का समग्र विकास का संवाहक बनाने के लिए एजेंडा।

- छोटे तथा मझौले उद्यम और विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र जो आज भी रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर सृजित करता है, की समस्याओं को दूर करने के लिए एजेंडा।

- इस सन्दर्भ में, मैं कहना चाहूंगा कि मैं ''द फार्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड'' के बारे में सी. के. प्रहलाद की थ्योरी से काफी प्रभावित हुआ हूं। मैं

गरीबी उन्मूलन के उनके दृष्टिकोण से सहमत हूं जिसमें यह कहा गया है कि ''यदि गरीब लोगों को पीड़ित अथवा बोझ समझना बंद कर दिया जाए और उन्हें समुत्थानशील व रचनात्मक उद्यमी और मूल्य–जागरूक उपभोक्ता के रूप में समझना शुरू कर दिया जाए तो अवसरों का एक सम्पूर्ण नया संसार खुलकर सामने आ जाएगा।

आइए, हम समाज के सबसे छोटे व्यक्ति को अधिकार–सम्पन्न बनाएं क्योंकि छोटा व्यक्ति ही राष्ट्र को शक्ति–सम्पन्न बनाएगा

- हमारे एजेंडा में भारत के शहरी क्षेत्रों के नवीकरण पर ज्यादा बल दिया जाएगा हमारे देश का बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमारे शहर तथा कस्बे आर्थिक विकास के मुख्य प्रेरक बन गए हैं। दुःख की बात यह है कि भारत की शहरी आबादी के सभी वर्गों के लिए जीवन की गुणवता बहुत साधारण है कुछ शहरों जैसे मुम्बई में नागरिक तथा आधारभूत ढांचा सम्बन्धी सुविधाओं की लगातार उपेक्षा के कारण स्थिति वास्तव में बहुत ही खराब है। जबकि मैं मुम्बईवासियों की जीवटता की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे उनकी दिन–प्रतिदिन की दुर्दशा के लिए वास्तव में दुख होता है।

- मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि अनियोजित शहरी विकास की बुराईयों को दूर करने के लिए सुशासन महत्वपूर्ण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण गुजरात है। यहां श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में न केवल सभी शहरों में अप्रत्याशित तरक्की देखी जा रही है बल्कि सरकार ने भी झुग्गी–झोपड़ियों (स्लम) की पुनर्स्थापना के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। जब मैं हाल में सम्पन्न हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के अभियान के लिए कर्नाटक गया था तो मैं शहरी मुद्दों के राजनैतिक महत्व को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गया। कर्नाटक में हमारी सफलता में मुख्य योगदानकर्ता बंगलुरू शहर में हमें मिला समर्थन था, जहां लोग पिछली सरकारों द्वारा व्यवस्थित शहरी विकास की उपेक्षा से तंग आ चुके थे। हमने अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा–पत्र में बंगलुरू को विश्व श्रेणी का शहर बनाने पर एक विस्तृत और सुविचारित अनुच्छेद शामिल किया और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री बी.एस. येदियुरप्पा के नेतृत्व में नई सरकार इस वायदे को पूरा करेगी।

- हमारा एजेंडा **भारत के युवाओं** के साथ मजबूत सम्बन्ध भी बनाएगा। इसके लिए हम भारत में उपलब्ध बृहद मानव संसाधनों को पुष्ट करने के लिए उच्च प्राथमिकता देंगे।

राजनीतिज्ञ के नाते मैं इस तथ्य से प्रभावित हूं कि अगले संसदीय चुनावों में लगभग 10 करोड़ नये मतदाता वोट डालेंगे।

मैं जानता हूं कि **देश के 18 साल से ऊपर के इन युवाओं का अपना कोई न कोई सपना होगा। वे बेहतर और सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं।**

उनके पास न केवल अपने लिए ही सपना है बल्कि भारत के लिए भी एक सपना है। वे भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जिसका विश्व समुदाय सम्मान करे और जो विश्व मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

हमारा यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य है कि उनके सपने पूरे हों।

इसके लिए मैं चाहूंगा कि सभी स्तरों पर विशेषकर उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा के स्तर पर उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए अवसरों में एक क्रान्तिकारी बढ़ोतरी होनी चाहिए।

हमें अनुसंधान और विकास के जरिए नये–नये क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं में विशेष रूप से सुधार लाना होगा।

मुझे बताया गया है कि भारत में प्रौद्योगिक क्षेत्रों में हर वर्ष लगभग 500 पी.एच.डी. शोध–पत्र तैयार किए जाते हैं। हमें कम से कम 5000 पी.एच.डी. शोध–पत्र तैयार करने चाहिए। अन्यथा हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों में योग्य अध्यापक कैसे उपलब्ध होंगे।

यह सब निजी तथा लोकहितैषी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा।

हमें एक ऐसा शैक्षिक आधारभूत ढांचा करना चाहिए जिसमें प्रत्येक युवा लड़के तथा लड़की को तरक्की करने का अवसर मिले।

मित्रो, किसी अन्य देश के विकास मॉडल की नकल करके भारत की समस्याएं दूर नहीं की जा सकती।

इसलिए मैंने हाल ही में एसोचेम के वार्षिक समारोह में बोलते हुए कहा था कि हम **विकास के भारतीय मॉडल** के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो हमारे लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो और हमारे अपने स्थानीय संसाधनों का अधिक

कारगर तरीके से इस्तेमाल करे, और पर्यावरण का ख्याल रखें यही हमारी सभ्यतागत परम्पराओं के मूल में निहित है।

इन्हीं शब्दों के साथ इस भव्य समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं श्री नाइनन को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

आप लोगों ने मेरे विचारों को बड़े धैर्यपूर्वक और रूचि लेकर सुना, उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद।

धन्यवाद